आधारभूत संरचना के विकास की चुनौती

संजय मधुकर नाफडे*

भारत ने इस वर्ष विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया जबकि उसका सकल घरेलू उत्पाद 3740 बिलियन डॉलर को पार कर गया, इस प्रकार उसने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे कर दिया। यद्यपि वह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में अभी भी कई देशों से पीछे है। देश ने वर्ष 2027-28 तक 5000 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है जिसे पूर्ण करना भारत के अब तक की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। पिछले दो-तीन वर्षों में कोविड व रूस यूक्रेन युद्ध सहित कई समस्याओं के साथ ही पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी के अंदेशे को देखते हुए भारत अपनी प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करने में लगा हुआ है, लेकिन उसे अपना नीति निर्धारण सुनिश्चित करने के साथ ही उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे कि वह दुनिया की पहली तीन आर्थिक महाशक्तियों में अपना स्थान बना सके, जिसके परिणामस्वरूप ही भारत देश वैश्विक बाज़ार व भू-राज नैतिक परिदृष्य में अपना स्थान बना सकता है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि भारत को आत्मनिर्भर बनना भी आवश्यक है, इससे वह अपनी अर्थव्यवस्था और घरेलू बाज़ार को अधिक प्रतियोगी बना सकता है। चूंकि भारत एक विकासशील देश है जिसके पास संसाधनों की एक सीमा है अत: इसका उपयोग उसे सावधानी से करने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में भारत को उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है जो अगले पांच वर्षों में उसके विकास के उद्देश्य को सही लक्ष्यों व योजनाओं के साथ चलने में समर्थ हो सकते हैं।

भारत की यह विशेषता ही है कि देश की अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों में जो आस्तियां एवं परिसंम्पतियाँ हैं, वह मात्र कारखानों, विशाल भवनों या मशीनरी के भौतिक ढांचे के रूप में ही नहीं हैं, जिनका उपयोग सामान और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है बल्कि मुख्य रूप से भारत की युवा आबादी और सामाजिक पूंजी जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ ही उसके विशाल प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी है जो इस विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान करते है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन सभी परिसंपत्तियों की उत्पादकता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि मूलभूत ढांचे के क्षेत्र के विकास मे इसका उपयोग किस प्रकार होता है। इसी को दृष्टिगत करते हुए व भारत के मूलभूत ढांचा क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रख कर पिछले वर्ष (2022-23) के केंद्रीय बजट में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की व्यवस्था की गई थी, जो भारत को सतत् विकास की और ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, चालू वर्ष (2023-24) के बजट में भी 75000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।

हम जानते है कि मूलभूत ढांचे का विकास आर्थिक प्रगति की अनिवार्य शर्त है, इससे उत्पादकता बढ़ती है और तमाम आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन की लागत कम होती है, पर्याप्त रूप से मूलभूत ढांचा उपलब्ध होना और उसका सटीक ढंग से चलना, देश के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्पादन में विविधता व नवोन्मेष लाना, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर व्यापार को बहुआयामी रूप प्रदान करना, पर्यावरण सुरक्षा को मूलभूत कारकों में शामिल करना तथा आमदनी से जुड़ने वाले कारकों में

*सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

सुधार लाकर बहुआयामी गरीबी के स्तर को सुधारना इसके महत्वपूर्ण कारक है, हालांकि भारत के मूलभूत ढांचे की विकास यात्रा ऐतिहासिक रूप से योजना को लागू करने की खामियों व असफलताओं की शिकार रही है। इसके अलावा भारत में हर क्षेत्र के लिए मौजूद नियमों की जटिलताओं ने भी देश में कारोबार के विकास पर विपरीत प्रभाव डाला है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना पर अनवरत काम करने की आवश्यकता है जिसे कि निरंतर एवं बहु आयामी निगरानी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। निश्चित रूप से इन अवसरों को समग्र और कुशल तरीक़े से लाभ उठाने के लिए भारत को अपने पुराने अनुभवों से सीख लेनी होगी, तभी देश बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सफल होगा।

मूलभूत ढांचे में निवेश और विकास

किसी भी देश के मूलभूत ढांचे में निवेश प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार इसका संचालन और रख-रखाव भी करती है। यह सारा व्यय पूंजीगत व्यय (capex) के तहत आता है और अर्थव्यवस्था में उत्पादक संपत्तियों के निर्माण का काम करता है। वैसे तो सरकार का किसी भी प्रकार का व्यय फिर चाहे वह राजस्व व्यय हो या पूंजीगत व्यय मांग पैदा करके उच्च स्तर के आर्थिक विकास को गति देता है। लेकिन दोनों तरह के व्यय का असर बिल्कुल भिन्न होता है। राजस्व व्यय, अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर मांग का कारक है जो मांग को उत्पन्न करता है जो कि अंतत: तेज़ आर्थिक विकास को गति देता है हालांकि इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में कोई इज़ाफ़ा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ़ सरकार जब मूलभूत ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत ख़र्च करती है, तो इससे न केवल सीधे तौर पर ठोस मांग पैदा होती है बल्कि इससे उत्पादकता में सुधार आता है और उत्पादन की लागत कम होती है। इन बातों के चलते निजी निवेश बढ़ता है और उनके लाभ की दर में वृद्धि होती है। यह बात भारत के संदर्भ में भी सही साबित होती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब सरकार एक रुपए का राजस्व व्यय (सीधे लोगों के खाते में भुगतान) करती है, तो उससे औसतन एक रुपए के बराबर ही अतिरिक्त आमदनी बढ़ जाती है। वहीं सरकार जब पूंजीगत व्यय में एक रुपए ख़र्च करती है तो ऐसा अनुमान है कि इससे आमदनी औसतन 2.45 रुपए बढ़ जाती है।

इसके अलावा विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के दौरान वित्तीय व्यय में वृद्धि होने से आय के चक्र को बढ़ावा मिलता है। लेकिन देखा यह गया है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबावों एवं अनुबन्धो के चलते दूसरे विकासशील देशों की तरह भारत द्वारा अपने व्यय पर लगाम लगाने की कोशिशें उसके पूंजीगत व्यय को भी सीमित कर देती हैं, ताकि बजट घाटा एक सीमा से आगे न बढ़े। इसका व्यापक असर होता है और अर्थव्यवस्था के उत्पादन एवं वृद्धि में कमी आती है। इसीलिए राजस्व व्यय का उपयोग व्यापक आर्थिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी को संतुलित बनाना बेहद अहम हो जाता है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि भारत के लिए आने वाले पच्चीस वर्ष (जिसे की अमृतकाल भी कहा गया है) अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले है, यह वह समय है जब कमजोरियों से मुक्ति पाने व अपनी शक्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से भारत की युवा आबादी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है।

यह कहा जा सकता है कि जहां मूलभूत ढांचे में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय की मांग बहुत अधिक होती है और इस व्यय से आमदनी में वृद्धि की संभावनाओं पर लम्बे समय बाद प्रभाव होता है। लेकिन इससे मूलभूत संरचना का निर्माण तीव्र गति से होता है। इसके अलावा मूलभूत ढांचे के विकास में तय समय-सीमा के तहत लक्ष्य आधारित निवेश भी बहुत अहम होते हैं। पहले की तरह मूलभूत ढांचे की मात्रा पर ज़ोर देने के बजाय, इसकी गुणवत्ता और कुशलता सुधारने को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने तीन बड़े उपाय सुझाए है। इन उपायों में कारोबार के मूल सिद्धांत जैसे कि प्रबंधन की स्वायत्तता देने जैसे सूत्र भी शामिल हैं, मूलभूत ढांचे को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और ग्राहकों समेत सभी साझीदारों की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही

में बढ़ोतरी करना शामिल है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पर्याप्त जवाबदेही के बिना यह क्षेत्र बेहद अकुशल साबित हो सकता है और इसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है।

भारत की प्राथमिकताएं क्या होना चाहिए?

भारत के तमाम सभी आर्थिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढती जा रही है एवं ऐसी स्थिति में व्यवसाय के लिए उत्कृष्ट मूलभूत ढांचे की ज़रूरत बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इस मामले में सरकार के सभी अंगों को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में मुख्य रूप से सड़क, जल मार्ग के साथ ही रेल और वायु सेवाओं के व्यापक जाल और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा का विकास शामिल है। वैसे तो भारत में पूंजीगत व्यय (सरकार के कुल ख़र्च के एक हिस्से के तौर पर) लगभग 23% ही है जो कि वैश्विक पैमानों से बेहद कम है। लेकिन पिछले पांच वर्षों के दौरान मूलभूत ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं में लगातार वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। मूलभूत ढांचे का क्षेत्र सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं के दायरे में आ गया है। 2019 से 2023 के दौरान स्थायी व सतत् आर्थिक प्रगति और देश के विकास के लिए इस क्षेत्र में 1400 बिलियन डॉलर के अनुमानित व्यय का अंदाज़ा लगाया गया है। इसके लिए भारत ने मूलभूत ढांचे के विकास के लिए कई क्षेत्रीय साझीदारों और विशेष रूप से जापान के साथ भी हाथ मिलाया है। यह कदम मूलभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति के एजेंडे को मज़बूती से आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इससे उम्मीद यही की जा रही है कि भारत अन्य क्षेत्रों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को अपने व्यावहारिक एवं व्यापारिक साझीदारों के साथ कार्यकारी समन्वय के साथ जोड़ेगा। इससे लेन-देन की लागत तो कम होगी ही, साथ ही तमाम देशों के साथ सामान और सेवाओं का बिना किसी बाधा के आदान-प्रदान भी हो सकेगा।

डॉलर मजबूत होने के कारण आयात बढने की आशंका के बीच सरकार को यह लगता है कि वह राजकोषीय घाटे को सीमित करने में सफल होगी। वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटा 6.71 प्रतिशत रहा था। अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत इस बात से मिलता है कि जीएसटी के संग्रहण में लगातार वृद्धि हो रही है (जून 2023 में 1,61,497 करोड़ रुपये तथा अक्टूबर 2023 में बढ़कर 1,72,000 करोड़), हालांकि यह महंगाई के कारण भी हो सकता है। देश में आर्थिक गतिविधियों के तेज होने के संकेत के रूप में उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज़ में लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकडों के अनुसार एसएमई व बडे उद्योगों को दिया जाने वाला ऋण बढकर जुलाई 2023 के अंत तक 32.82 लाख करोड रुपये हो गया है। देश की आर्थिक विकास की दर के बारे में विभिन्न विचार व्यक्त किए जाते रहते है, अनेक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि यह वृद्धि अगर 7 से 7.5 प्रतिशत के बीच भी रहती है तो एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक देश के प्रति व्यक्ति आय 70% तक बढकर 4000 डॉलर हो सकती है जिसके फलस्वरूप देश का सकल घरेलू उत्पाद कोई 6 ट्रिलियन के आसपास होगा, जिसका आधे से अधिक हिस्सा घरेलू खपत से प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 460 डॉलर ही थी। इसी वृद्धि दर से वर्ष 2047 तक भारत देश एक मध्य आय वाला देश बनने में समर्थ हो सकता है, ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था का आकार बीस लाख करोड़ डॉलर होगा व आय प्रति व्यक्ति दस हजार डॉलर प्रतिवर्ष हो सकती है।

इंडिया कम्पीटिटीवनेस इनिशिअटिव की एक रिपोर्ट का हवाला देना यहां उचित होगा क्योंकि इसमें कई मानकों का इस्तेमाल कर प्रतिस्पर्धी क्षमता का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समय के साथ भारत में गरीबी तो कम हुई है परंतु असमानता में चिंताजनक वृद्धि हुई है और देश की सम्पत्ति कुछ सीमित धनाढ्य वर्ग के हाथ में केंद्रित होती जा रही है। जहां देश में प्रति कर्मचारी सकल घरेलू उत्पाद में आए बदलाव के आधार पर उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन श्रम का यथोचित प्रबंधन नहीं किया जा सका है, क्योंकि भारत कृषि व श्रम शक्ति भागीदारी से अधिक लोगों को श्रम के लिए जुटाने में सफल नहीं हो पाया है। जहां

एक ओर बड़ी कम्पनियों ने उत्पादकता वृद्धि को गति दी है, वही दूसरी ओर छोटी व कमजोर भारतीय कंपनिया, जिनकी सकल घरेलू उत्पाद व रोजगार में बड़ी हिस्सेदारी है, में समस्याएं बनी हुई है। एक नियोजित प्रक्रिया के अंतर्गत देश में उच्च गुणवत्ता की कंपनियों का उभार हुआ है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही इनकी गुणवत्ता व लाभप्रदता भी बढी है, सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य वर्ष 1991 से 1999 के बीच हुआ, सीमा शुल्क में कमी का इसमें बड़ा योगदान रहा है। देश में संस्थागत सुधारों की दिशा में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता बनी हुई है।

हालांकि परिवहन और डिजिटल संयोजकता के मूलभूत ढांचे के विकास में भारी निवेश के साथ ही भारत में केंद्र और राज्यों की सरकारों के तमाम विभागों के बीच कुशल तालमेल बढ़ाने की भी आवश्यकता है। वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत अधिक है। इसकी वजह कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं और जिनका तुरंत समाधान निकालने की आवश्यकता है। तभी जाकर 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर योजना' के अंतर्गत मूलभूत ढांचे के विकास की परिकल्पना को आपसी तालमेल से साकार किया जा सकेगा और इससे मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क के जरिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना बाधा के संपर्क को सुनिश्चित किया जा सकेगा और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा, जो आर्थिक प्रगति और विकास में योगदान दे सकेंगे। इसके साथ ही सतत् विकास के एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर योजना के माध्यम से औद्योगिक विकास और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना भारत की अर्थव्यवस्था को हरित परिवर्तन की राह पर भी ले जा सकने में समर्थ होगा। एक अन्य चिंताजनक तथ्य उभरकर सामने आता है, वह यह है कि जहां ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन लगातार बढ रहा है लेकिन शहरीकरण की प्रक्रिया एवं वहाँ उपलब्ध सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में भारत के लिए सबसे अहम कार्य मूलभूत ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं में भारी निवेश की कोशिशों और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक तत्वों के बीच समन्वय बैठाना होगा। मूलभूत ढांचे के विकास के लिए आवश्यक और आपस में जुड़ी इन चुनौतियों से समग्र रुप से निपटकर ही भारत अगले एक दशक के दौरान अपने विकास की संभावनाओं को साकार कर सकेगा।

स्त्रोत

- नीति आयोग
- भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न सूचना पत्र तथा विभिन्न समाचार पत्रों की सामग्री
- इकोनोमिक टाइम्स
- https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/centres-fiscal-deficit-narrows-down-to-64-of-gdp-meets-set-budgeted-target-383647-2023-05-31
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1936636

Bank Quest Articles - Honorarium for the Contributors

Contribution	Amount
Article / Research Paper	₹ 7,500/-
Book Review	₹ 3,000/-
Legal Decisions affecting Bankers	₹ 3,000/-